नईदुनिया

ईरान में सत्ता संघर्ष गहराया, समझौते पर बढ़ा विवाद

सरकार पर अमेरिका के सामने झुकने के आरोप, कट्टरपंथी धड़े ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खोला मोर्चा

तेहरान, एजेंसीः अमेरिका के साथ युद्धविराम समझौते के बाद ईरान में राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। राष्ट्रपति मसूद पजशकियान, विदेश मंत्री अब्बास अराघची तथा संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ पर कट्टरपंथी धड़े ने अमेरिका के साथ समझौता कर देश के मूल सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाया है। अंतरराष्ट्रीय समाचार माध्यमों की रिपोर्टों के अनुसार तेहरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी यह नाराजगी सार्वजनिक रूप से दिखाई दी।

अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति मसूद पजशकियान के विरुद्ध नारे लगाए गए, जबकि विदेश मंत्री अब्बास अराघची पर पथराव किए जाने का दावा किया गया। कट्टरपंथी धड़े का आरोप है कि सरकार ने अमेरिका के साथ समझौता कर देश की नीतियों से समझौता किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। कट्टरपंथियों का कहना है कि अमेरिका के साथ समझौता नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई की इच्छाओं के विपरीत हुआ। मुजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और उन्होंने देश को कोई सार्वजनिक संबोधन भी नहीं दिया है। इस स्थिति को लेकर भी राजनीतिक अटकलें तेज हैं।

रिपोर्टों के अनुसार सरकार और कट्टरपंथी धड़े के बीच मतभेद केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संसद के भीतर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। हाल ही में संसद के विशेष सत्र में अमेरिका के साथ समझौते का विरोध करने वाले दो प्रमुख कट्टरपंथी सांसदों को महत्वपूर्ण संसदीय पदों से हटा दिया गया। इसे सत्ता संतुलन में बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मौजूदा सरकार कट्टरपंथी धड़े के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि इन समूहों का प्रभाव संसद और सरकारी संस्थानों में अब भी बना हुआ है। उनके अनुसार सरकार और कट्टरपंथियों के बीच मतभेद अवश्य हैं, लेकिन दोनों पक्षों की प्राथमिकता देश के हितों की रक्षा, युद्ध की समाप्ति, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत तथा होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रभाव बनाए रखना है। इसी बीच कट्टरपंथी नेताओं की ओर से अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है। उनका मानना है कि युद्धविराम के बजाय टकराव की नीति जारी रखी जानी चाहिए।

दूसरी ओर सरकार कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से तनाव कम करने और आर्थिक प्रतिबंधों में राहत प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसे में ईरान की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति दोनों पर इस सत्ता संघर्ष का प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

चिंग-ते बोले - ताइवान अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करेगा

राष्ट्रपति ने चीन के बढ़ते दबाव के बीच एकजुट रहने का आह्वान किया

ताइपे, एजेंसीः ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा है कि देश को अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए एकजुट रहना होगा और किसी भी परिस्थिति में लोकतांत्रिक ताइवान को चीन का ताइवान नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चीन के बढ़ते दबाव का मिलकर सामना करने का आह्वान किया।

पार्टी के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शांति के समय भी ताइवान को पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चीन का नया जातीय एकता कानून बीजिंग को अपनी सीमाओं के बाहर रहने वाले लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई का आधार प्रदान करता है। ताइवान को आशंका है कि इस कानून का उपयोग उन ताइवानी नागरिकों के विरुद्ध किया जा सकता है, जिन्हें चीन अलगाववादी मानता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान पर चीन की कानूनी व्यवस्था का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पार्टी नेताओं से समाज को चीन के बढ़ते दबाव और भय के वातावरण के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

लाई चिंग-ते ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र जीवनशैली की रक्षा के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने दोहराया कि ताइवान पहले से ही एक स्वतंत्र देश है, जिसका संवैधानिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है और वह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अधीन नहीं है।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पिछले एक दशक के दौरान उनकी पार्टी की सरकार ने चीन के बढ़ते दबाव, दुष्प्रचार, सैन्य धमकियों और कूटनीतिक दबाव के सामने कभी पीछे हटने का मार्ग नहीं चुना।

एटीएम ठगी गिरोह का सरगना गिरफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबईः महाराष्ट्र के मुंबई स्थित भांडुप क्षेत्र में पुलिस ने एटीएम से नकदी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उसके सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम मशीन के नकदी निकलने वाले स्थान पर प्लास्टिक की पतली पट्टी फंसा देते थे, जिससे रुपये बाहर नहीं निकलते थे और ग्राहक ठगी का शिकार हो जाते थे।

पुलिस के अनुसार इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो महिलाओं की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक ऑफ बड़ौदा की भांडुप शाखा प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई कि कई ग्राहकों के खातों से राशि कटने के बावजूद एटीएम से नकदी नहीं निकली। बैंक को इस प्रकार की पांच शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

जांच में सामने आया कि ग्राहक लेनदेन असफल समझकर वहां से चले जाते थे। इसके बाद आरोपी वापस आकर मशीन में फंसी नकदी निकाल लेते थे। निगरानी चित्रों तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद जियाद उर्फ अयान इरशाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने मामले में दो महिलाओं की पहचान भी की है। कार्रवाई के दौरान 80 हजार रुपये मूल्य की एक मोटरसाइकिल, 10 हजार रुपये मूल्य का एक मोबाइल दूरभाष, अपराध में प्रयुक्त प्लास्टिक की पट्टियां तथा 39 हजार 500 रुपये की चोरी की नकदी बरामद की गई है। जब्त सामग्री का कुल मूल्य लगभग 1.29 लाख रुपये बताया गया है। पुलिस को संदेह है कि गिरोह ने अन्य एटीएम केंद्रों पर भी इसी प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है और इसकी जांच जारी है।

समुद्र में 116 लोगों को लेकर जा रही नौका पलटी

जॉर्जटाउन, एजेंसीः दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में 116 यात्रियों और चालक दल को लेकर जा रही एमवी बरिमा यात्री नौका समुद्र में पलट गई। अधिकारियों के अनुसार अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि शेष लोगों की तलाश के लिए व्यापक खोज एवं बचाव अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार यात्री नौका राजधानी जॉर्जटाउन से उत्तरी अटलांटिक तट के मार्ग से पोर्ट कैटुमा जा रही थी। दुर्घटना पोमेरून नदी के निकट हुई। स्थानीय समयानुसार रात 11 बजकर एक मिनट पर संकट संदेश प्राप्त होने के बाद सरकारी एजेंसियों तथा निजी नौकाओं की सहायता से तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

नेतन्याहू की संभावित यात्रा पर न्यूयॉर्क में बढ़ा विवाद

महापौर ने गिरफ्तारी की कानूनी संभावना पर विचार की बात कही, इजराइल ने किया कड़ा विरोध

न्यूयॉर्क, एजेंसीः संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संभावित न्यूयॉर्क यात्रा को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। न्यूयॉर्क के महापौर जोहरान ममदानी ने कहा है कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए शहर आने पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की कानूनी संभावना पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर के विधि विभाग के साथ चर्चा चल रही है।

ममदानी ने कहा कि वह वही कदम उठाएंगे, जिसकी कानून अनुमति देगा। उनका कहना है कि उनके विचार में नेतन्याहू का स्थान हेग में है, जहां अंतरराष्ट्रीय अपराधों के आरोपित व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई होती है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नवंबर 2024 में गाजा में कथित युद्ध अपराध तथा मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों को लेकर नेतन्याहू के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ममदानी ने एक साक्षात्कार में कहा कि नेतन्याहू युद्ध अपराधों के आरोपी हैं और अनेक लोग ऐसा मानते हैं।

दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने महापौर के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर यहूदी विरोधी वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं और इजराइल के विरुद्ध माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डैनन ने यह भी पुष्टि की कि नेतन्याहू 22 से 28 सितंबर के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह में संबोधन करेंगे। उनका कहना है कि महापौर के रुख से इस कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस बीच नेतन्याहू भी पहले कह चुके हैं कि उन्हें गिरफ्तारी संबंधी बयानों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने महापौर पर हमास का समर्थन करने और अमेरिका के प्रति विरोधी रुख रखने का आरोप लगाया था।

गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल, दोनों अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सदस्य नहीं हैं। अमेरिकी संघीय कानून के अनुसार राज्य और स्थानीय प्रशासन न्यायालय के अनुरोधों पर सहयोग नहीं कर सकते। पिछले वर्ष न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल भी कह चुकी हैं कि महापौर के पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।

कनाडा के जंगल में आग, धुएं से अमेरिका के कई शहर प्रभावित

टोरंटो, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से बिगड़ी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह

टोरंटो, एजेंसीः कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग का धुआं अमेरिका तक पहुंचने से टोरंटो, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो गई है। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने तथा सावधानी बरतने की सलाह दी है।

कनाडा में इस समय 955 स्थानों पर जंगलों में आग लगी हुई है। इनमें से लगभग 200 स्थान केवल ओंटारियो प्रांत में हैं। कई क्षेत्रों में आग अब भी नियंत्रण से बाहर बनी हुई है। वहीं अमेरिका के मिनेसोटा राज्य की उत्तरी सीमा पर भी एक दर्जन से अधिक स्थानों पर वनाग्नि फैली हुई है, जिसने 73 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। अधिकारियों ने स्थिति को अभूतपूर्व बताते हुए आपातकाल घोषित किया है।

अमेरिका के राष्ट्रीय अग्नि समन्वय केंद्र तथा कनाडा के प्राकृतिक संसाधन विभाग के अनुसार जून के अंतिम दिनों में लगातार गर्म मौसम और सामान्य से कम वर्षा के कारण आग तेजी से फैली। उपग्रह चित्रों में धुआं ओंटारियो से टोरंटो, न्यूयॉर्क राज्य और बोस्टन तक पहुंचता दिखाई दिया।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडा पर वनाग्नि रोकने में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इन आरोपों को अनुचित बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि वनाग्नि के धुएं के लिए केवल कनाडा को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि धुआं हवा की दिशा के साथ सीमाओं को पार कर दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच जाता है।

कम वर्षा से कर्नाटक में गहराया जल संकट, पेयजल आपूर्ति प्रभावित

मानसून में 39 प्रतिशत कमी से जलाशय खाली

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरुः कर्नाटक में दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से 39 प्रतिशत कम रहने के कारण पेयजल और कृषि संकट गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बताया कि कम वर्षा के कारण जलाशयों में जल भंडार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधा रह गया है, जिससे खेती और पेयजल आपूर्ति दोनों प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 26 जिलों के 158 तालुकों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि 20 तालुकों में गंभीर जल संकट की स्थिति है। विजयनगर जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां वर्षा में 67 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

राज्य के प्रमुख जलाशयों में वर्तमान में 359.98 टीएमसी जल उपलब्ध है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 681.83 टीएमसी था। कई पनबिजली जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का केवल 23 प्रतिशत जल शेष है।

कम वर्षा का असर खरीफ फसलों की बुवाई पर भी पड़ा है। 84.10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 43.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हो सकी है। राज्य के 539 ग्राम पंचायत क्षेत्रों से पेयजल संकट की सूचना मिली है। 112 गांवों में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, जबकि 622 गांवों की जरूरत पूरी करने के लिए 725 निजी नलकूप किराये पर लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने, खराब जल शुद्धीकरण संयंत्रों की तत्काल मरम्मत कराने तथा जनप्रतिनिधियों को प्रभावित क्षेत्रों का नियमित दौरा करने के निर्देश भी दिए हैं।

विधायक रिश्वत प्रकरण में दो कारोबारी गिरफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, चेन्नईः तमिलनाडु में सत्तारूढ़ टीवीके के एक विधायक को कथित रूप से 35 करोड़ रुपये की रिश्वत देकर पक्ष बदलवाने के मामले में पुलिस ने एक वित्त कंपनी के दो संचालकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कार्यालय से 2 करोड़ 82 लाख 49 हजार रुपये की बेहिसाब नकदी भी जब्त की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार ऊथनगराई से विधायक डॉ. एन. एलयाराजा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

विधायक ने आरोप लगाया था कि एक यूट्यूबर और जनमत सर्वेक्षण संस्था के संचालक थिरुनावुक्कारसु ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें 35 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी। आरोप है कि प्रस्ताव ठुकराने पर विधायक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस को जानकारी मिली कि रिश्वत के लिए दी गई अग्रिम राशि शहर के चूलैमेडु क्षेत्र स्थित एक वित्त कंपनी में जमा कराई गई थी। इसके बाद छापेमारी में 2 करोड़ 82 लाख 49 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ के बाद कंपनी के संचालक करुणानिधि और सरवनन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि बरामद राशि उन्हें पहले से गिरफ्तार एक आरोपी ने सौंपी थी।

कार्रवाई *बिना वैध दस्तावेज वाले भारतीयों पर कार्रवाई तेज, अपील और सुनवाई का अवसर नहीं मिलने की आशंका*

अमेरिका से 18 हजार भारतीयों के निर्वासन की तैयारी

न्यूयॉर्क, एजेंसीः अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने बिना वैध दस्तावेज के रह रहे प्रवासियों के विरुद्ध बड़े स्तर पर निर्वासन अभियान की तैयारी तेज कर दी है। इस कार्रवाई के दायरे में लगभग 18 हजार भारतीयों के आने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन एक बार फिर निर्वासन के लिए सैन्य विमानों का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है, जो उसकी सख्त आव्रजन नीति का प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार बिना वैध दस्तावेज वाले भारतीयों को इस कार्रवाई के दौरान अपील, सुनवाई अथवा विधिक सहायता का अवसर मिलने की संभावना नहीं है। अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी की टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले रही हैं।

प्रवासी नागरिकों को रखने के लिए प्रशासन ने एल पासो तथा कैलिफोर्निया में नए भवन खरीदे हैं, जिन्हें हिरासत केंद्रों में परिवर्तित कर संबंधित एजेंसी को सौंप दिया गया है। इन केंद्रों में लगभग 12 हजार लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है।

न्यूयॉर्क के आव्रजन मामलों के अधिवक्ता ग्रेग सिस्किंड का कहना है कि पहले बिना वैध दस्तावेज वाले लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता था, लेकिन

अब कई मामलों में लोगों को सीधे हिरासत केंद्र भेजा जा रहा है। उनके अनुसार अमेरिका की संघीय व्यवस्था में विभिन्न राज्यों के मानवाधिकार संबंधी नियम अलग-अलग हैं, फिर भी कार्रवाई पूरे देश में की जा रही है।

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अमेरिका ने 3,567 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया था। वहीं वर्ष 2026 में जून तक 1,076 भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि 5 फरवरी 2025 को अमेरिका ने पहली बार सैन्य विमान के माध्यम से 104 भारतीय नागरिकों को अमृतसर भेजा था। उस समय कई लोगों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर लाए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद व्यापक विवाद हुआ था। इस मुद्दे पर देशभर में प्रतिक्रिया हुई थी और संसद में भी इसे लेकर तीखी चर्चा हुई थी।